	1	2	3
46.	बांका	412.31	414.60
47.	जमुई	793.82	887.56
48.	गढ़वा	1065.25	1189.16
49.	चतरा	1046.81	1196.83
50.	बोकारो	851.37	953.10
	कुल :	42964.66	49296.96

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की निगरानी

929. **श्री नागमणि** : **क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, केन्द्रीय स्वर्ग से अधिकारियों की नियुक्ति करके जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कार्य की निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के मौजूदा लेखा स्कंधों को सुद्धढ़ करने के विचार से राज्यों के केन्द्रीय अथवा राज्य लेखा सेवा संवर्ग के प्रति अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की सलाह दी गई है ।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के कार्यक्रमों का अवलोकन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए, राज्यों को राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तरों पर सतर्कता तथा निगरानी समितियां बनाने की सलाह दी गई है । इन समितियों में जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगें ।

Expansion of Aluminium plants

930. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the present capacity of each and every Aluminium plant in the country;

(b) whether Government have a proposal to expand some of those units; and

(c) if so, the details of those Aluminium plants which are being selected for expansion?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) Existing Capacities of primary producers of aluminium in Public Sector and Private Sector are given below:-Public Sector Companies:

NALCO - 2.18,000 Tonnes

BALCO 1.00.000 Tonnes

Private Sector Companies.

INDAL - 1,17,000 Tonnes

H1NDALCO - 2,10,000 Tonnes

MALCO - 25,000 Tonnes

(b) and (c) Government's approval is not required for expansion of capacity in Private Sector Companies. However, with respect to National Aluminium Company Limited (NALCO). There is a proposal to expand the capacity to 3,45,000 Tonnes per annum.

मत्स्य-विकास विभाग की योजनाएं

931. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मत्स्य-विकास विभाग द्वारा, माह फरवरी, 1994 में, जलाशयों में मत्स्य-विपणन योजना के तहत पांच योजनाएं, जिनकी कुल लागत 4.50 करोड़ रुपये है, कृषि मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से अंतर्देशीय मत्स्य विपणन योजना के तहत लगभग 4.35 करोड़ रुपये की लागत की पांच इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव फरवरी, 1994 में प्राप्त हुए थे । चूंकि अंतर्देशीय मत्स्य विपणन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना का परिव्यय इसके वर्तमान स्तर पर रोक दिया गया है इसलिए उस योजना के अंतर्गत किसी भी नये प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं की जा सकी ।

National Mahila Krishi Kendra

932. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the training imparted to the women agriculturists in National Mahila Krishi Kendra; and

(b) the number of such "Mahila Krishi Kendra" functioning in the country?